

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
(सिविल रिट क्षेत्राधिकार)
रिट याचिका (कर) संख्या 5475/2023

मेसर्स एनविल केबल्स प्राइवेट लिमिटेड, एक निजी लिमिटेड कंपनी है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित और अस्तित्व में है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 102 कृष्णा, 224, एजेसी बोस रोड, डाकघर और थाना- एजेसी बोस रोड, जिला- कोलकाता- 700017 है, जो अपने गठित वकील श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, उम्र लगभग 50 वर्ष, पुत्र श्री रवींद्र नाथ सिंह, निवासी दीवानजी स्ट्रीट, हुगली, डाकघर और थाना- रिशारा, जिला- हुगली, पिन कोड- 711228, पश्चिम बंगाल के माध्यम से है।

.... याचिकाकर्ता

बनाम

- झारखंड राज्य, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के माध्यम से, जिसका कार्यालय एसबीआई बिल्डिंग, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर और थाना- धुर्वा, जिला-रांची, झारखंड-834004 में है।
- झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, एक राज्य सरकार की कंपनी, जिसका पंजीकृत पता इंजीनियरिंग बिल्डिंग, एच.ई.सी., धुर्वा, डाकघर और थाना धुर्वा, जिला-रांची, झारखंड-834004 है।
- अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, जिसका कार्यालय इंजीनियरिंग बिल्डिंग, एच.ई.सी., धुर्वा, डाकघर और थाना धुर्वा, जिला-रांची, झारखंड-834004 है।
- वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त एवं लेखा), झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, जिसका कार्यालय इंजीनियरिंग बिल्डिंग, एच.ई.सी., धुर्वा, डाकघर और थाना- धुर्वा, जिला-रांची, झारखंड -834004 है।
- संयुक्त आयकर आयुक्त (टीडीएस), जिसका कार्यालय आयकर बिल्डिंग, एम.जी. रोड, डाकघर-रेलवे डाकघर और थाना- चुटिया, जिला-रांची-834001 है।

...प्रतिवादी

कॉरम: माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
माननीय न्यायमूर्ति नवनीत कुमार

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री एम.एस. मित्तल, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री राहुल लांबा, अधिवक्ता
श्री सलोना मित्तल, अधिवक्ता
जेबीवीएनएल की ओर से : श्री राजीव रंजन, महाधिवक्ता
श्री सचिन कुमार, वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता
आयकर विभाग की ओर से : श्री अनुराग विजय, स्थायी अधिवक्ता
श्री ओम प्रकाश, स्थायी अधिवक्ता के सहायक
श्री शिवम सिंह, स्थायी अधिवक्ता के सहायक

8 अप्रैल 2024

प्रति, श्री चंद्रशेखर, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

मेसर्स एनविल केबल्स प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है:

i. प्रतिवादी जेबीवीएनएल को निर्देश देने के लिए उचित रिट/आदेश/निर्देश या परमादेश की प्रकृति में रिट जारी करने के लिए कि वह प्रतिवादी जेबीवीएनएल को सामग्री की आपूर्ति के लिए याचिकाकर्ता द्वारा जारी किए गए बिलों से 2% की दर से आयकर के रूप में काटे गए 2,90,32,000/- रुपये की राशि के लिए टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करे ताकि याचिकाकर्ता को आयकर कानूनों के तहत उक्त राशि का टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके; या वैकल्पिक रूप से।

ii. प्रार्थना (i) के विकल्प में, प्रतिवादी जेबीवीएनएल को निर्देश देने के लिए एक उचित रिट/आदेश/निर्देश या परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करने के लिए, जो याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी जेबीवीएनएल को सामग्री की आपूर्ति के लिए याचिकाकर्ता के बिलों से काटे गए 2,92,32,000/- रुपये की राशि को तुरंत जारी करने का निर्देश दे, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों के बावजूद, प्रतिवादी जेबीवीएनएल ने न तो आज तक उक्त राशि जारी की है और न ही प्रतिवादी जेबीवीएनएल द्वारा आयकर कानून के तहत टीडीएस प्रमाण पत्र जारी किया गया है ताकि याचिकाकर्ता को उक्त राशि का टीडीएस क्रेडिट लेने का अधिकार मिल सके।

iii. याचिकाकर्ता के साथ विवेकपूर्ण न्याय करने के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर किसी अन्य उपयुक्त रिट या निर्देश या आदेश जारी करने के लिए, जैसा कि यह माननीय न्यायालय उचित और उचित समझे।

2. याचिकाकर्ता फर्म कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत है और भारत में कोर सेक्टर उद्योगों को व्यापक इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है। इसने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) द्वारा सामग्री की आपूर्ति के लिए जारी किए गए चालू खाते के बिलों से 2,90,32,000 रुपये की कटौती करने की कार्रवाई को चुनौती दी है।

3. याचिकाकर्ता फर्म को दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत गिरिडीह, बोकारो और धनबाद में बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए चुना गया था। बाद में, जेबीवीएनएल ने झारखंड राज्य के उपर्युक्त जिलों के लिए (i) सामग्री की आपूर्ति के लिए एलओए संख्या 01/आरई दिनांक 5 फरवरी 2016, एलओए संख्या 03/आरई दिनांक 5 फरवरी 2016 और एलओए संख्या 05/आरई दिनांक 5 फरवरी 2016 के अनुसार पुरस्कार पत्र जारी किए और (ii) निर्माण और सिविल कार्यों के लिए एलओए संख्या 02/आरई दिनांक 5 फरवरी 2016, एलओए संख्या 04/आरई दिनांक 5 फरवरी 2016 और एलओए संख्या 06/आरई दिनांक 5 फरवरी 2016 के अनुसार पुरस्कार पत्र जारी किए। जेबीवीएनएल ने याचिकाकर्ता फर्म द्वारा सामग्री आपूर्ति के लिए जारी किए गए चालू बिलों से 2% की दर से कटौती शुरू कर दी और आयकर आकस्मिकता के बहाने 2,90,32,000/- रुपए अपने पास रख लिए। कई संचारों के माध्यम से, याचिकाकर्ता फर्म ने जेबीवीएनएल से आयकर आकस्मिकता के रूप में रोकी गई राशि को जारी करने का अनुरोध किया और जेबीवीएनएल को यह भी सूचित किया कि उसके द्वारा रोकी गई राशि फॉर्म-26एएस में नहीं दिखाई देती है। इसके बावजूद, जेबीवीएनएल ने अवैध रूप से काटी गई राशि को जारी नहीं किया और न ही उक्त राशि को आयकर विभाग में जमा किया।

4. जेबीवीएनएल ने आधार बनाया है कि उसने याचिकाकर्ता फर्म के चालू बिल से 2% की दर से कटौती की है और 2,90,32,000/- रुपये की राशि अपने हितों की रक्षा के लिए "वापस रख ली गई" है। इसने दलील दी है कि 10 अक्टूबर 2017 के डिमांड नोटिस के खिलाफ जेबीवीएनएल द्वारा पेश की गई अपील के नतीजे के आधार पर "वापस रखी गई" राशि जारी की जाएगी या टीडीएस प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। जवाबी हलफनामे में जेबीवीएनएल ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 201 के तहत नोटिस और डिमांड नोटिस का हवाला दिया जिसमें टीडीएस कटौती के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माना और दंड ब्याज शामिल है। यह कहा गया है कि डिमांड नोटिस के खिलाफ जेबीवीएनएल ने 5 दिसंबर 2017 को फॉर्म नंबर 35 के जरिए सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील दायर की है; पावती संख्या 325620911051217.

5. जेबीवीएनएल ने अपने जवाबी हलफनामे में निम्नलिखित रुख अपनाया:

5. यह कहा गया है और प्रस्तुत किया गया है कि उत्तर के तहत रिट याचिका के पैराग्राफ-1 में दिए गए बयानों के संबंध में यह कहा गया है कि रिट आवेदन, जिसमें याचिकाकर्ता ने बिंदु संख्या i, ii, iii और iv में राहत के लिए प्रार्थना की है, नीचे उद्धृत निम्नलिखित तथ्यों के प्रकाश में स्वीकार्य नहीं है:

शुरू में जेबीवीएनएल सामग्री की आपूर्ति के खिलाफ किए गए भुगतान पर आयकर पर टीडीएस नहीं काट रहा था। दिनांक 10.08.17 को आयकर विभाग ने जेबीवीएनएल में एक सर्वेक्षण किया और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 201 के तहत एक नोटिस जारी किया, संदर्भ संख्या डी सीआईटी/आरएएन/टीडीएस/2017-18/177 दिनांक 04.09.17।

उक्त नोटिस में विभाग ने कहा कि अनुबंध सभी कार्यों के लिए है, जिसमें सामग्री की आपूर्ति भी शामिल है, जिसे केवल सामग्री की आपूर्ति नहीं माना जा सकता, क्योंकि आपूर्ति भाग के लिए एक अलग अनुबंध है। बल्कि ठेकेदार अनुबंध के लिए उपयोग करने के लिए सामग्री खरीद रहा है। उन्होंने इसे एक समग्र अनुबंध के रूप में माना। सुनवाई के बाद, विभाग ने अपने ज्ञापन संख्या 607 दिनांक 10.10.17 के तहत 36,63,51,685.00 रुपये के लिए ब्याज के साथ टीडीएस की राशि जमा करने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया। बाद में अनुरोध प्रस्तुत करने के बाद उक्त मांग को संशोधित कर केवल 9,79,04,575/- रुपये कर दिया गया। इस राशि में टीडीएस राशि की कटौती न करने के लिए दंडात्मक ब्याज के साथ जुर्माना भी शामिल है।

इसके अलावा, जेबीवीएनएल ने विभाग द्वारा की गई मांग के खिलाफ सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील दायर की। आयकर अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार, विभाग ने डिमांड नोटिस का 20% यानी 1,95,80,915/- रुपये दो अलग-अलग चालान के माध्यम से 1,46,32,395/- और 49,48,52/- रुपये जमा कर दिए हैं। अपील 05.12.2017 को दायर की गई थी। हालाँकि, मामले में अभी भी निर्णय का इंतजार है।

उपरोक्त के आलोक में, आयकर विभाग द्वारा उक्त डिमांड नोटिस में लगाए गए टीडीएस और ब्याज की राशि को जेबीवीएनएल के हितों की रक्षा के लिए एजेंसी के बिलों से वापस रखा जाता है। तदनुसार, वापस रखी गई राशि एजेंसी को जारी कर दी जाएगी या अपील के परिणाम के आधार पर टीडीएस प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तदनुसार, बिंदु 1 (i, ii, iii, iv) में एजेंसी द्वारा किए गए दावे उपरोक्त उद्धृत तथ्यों के आधार पर मान्य नहीं हैं।

6. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम.एस. मित्तल ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता फर्म जेबीवीएनएल और आयकर विभाग के बीच विवाद में पक्ष नहीं है, और टीडीएस प्रमाणपत्र जारी किए बिना

2,90,32,000/- रुपये रोकना मनमाना और गैरकानूनी है। यह प्रस्तुत किया गया है कि 2,90,32,000/- रुपये जारी न करके याचिकाकर्ता फर्म को जेबीवीएनएल द्वारा दंडित किया जा रहा है। आयकर विभाग द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि जेबीवीएनएल चूककर्ता करदाता है और विभाग ने उसे याचिकाकर्ता फर्म के चालू बिलों से कोई टीडीएस रोकने/रखने का निर्देश कभी नहीं दिया। आयकर विभाग के विद्वान अधिवक्ता ने इस संबंध में आयकर अधिनियम के तहत प्रावधानों का हवाला दिया।

7. आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी राशि की कटौती या भुगतान न करने पर आयकर अधिनियम की धारा 201 के तहत दिए गए परिणाम भुगतान होंगे; ऐसे परिणामों में से एक उस पर ब्याज लगाना है। आयकर अधिनियम की धारा 203 में प्रावधान है कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर की कटौती करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, राशि के क्रेडिट या भुगतान के समय से या जैसा भी मामला हो, किसी शेयरधारक को किसी लाभांश के भुगतान के लिए चेक या वारंट जारी करने के समय से निर्धारित अवधि के भीतर उस व्यक्ति को, जिसके खाते में ऐसा क्रेडिट दिया गया है या जिसे ऐसा भुगतान किया गया है या चेक या वारंट जारी किया गया है, इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रदान करेगा कि कर काट लिया गया है, और इस प्रकार कटौती की गई राशि, जिस दर पर कर काटा गया है और ऐसे अन्य विवरण जो निर्धारित किए जा सकते हैं, निर्दिष्ट करता है। आयकर अधिनियम की धारा 201 और 203 में निम्नानुसार प्रावधान है:

201. कटौती करने या भुगतान करने में विफलता के परिणाम.--(1) जहां कोई व्यक्ति, जिसमें किसी कंपनी का प्रधान अधिकारी भी शामिल है,-

(क) जिसे इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई राशि कटौती करने की आवश्यकता है; या

(ख) धारा 192 की उपधारा (1-ए) में निर्दिष्ट, नियोक्ता होने के नाते, इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत अपेक्षित कर के पूरे या किसी हिस्से की कटौती नहीं करता है, या भुगतान नहीं करता है, या कटौती करने के बाद भुगतान करने में विफल रहता है, तो ऐसा व्यक्ति, किसी भी अन्य परिणाम के पूर्वाग्रह के बिना, जो उसे भुगतान पड़ सकता है, ऐसे कर के संबंध में चूक करने वाला करदाता माना जाएगा:

बशर्ते कि कोई व्यक्ति, जिसमें कंपनी का प्रधान अधिकारी भी शामिल है, जो किसी निवासी को भुगतान की गई राशि या किसी निवासी के खाते में जमा की गई राशि पर इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार कर का पूरा या उसका कोई भाग काटने में विफल रहता है, तो उसे ऐसे कर के संबंध में चूककर्ता करदाता नहीं माना जाएगा, यदि ऐसा निवासी-

(i) धारा 139 के तहत अपनी आय का रिटर्न प्रस्तुत कर चुका है;

(ii) ऐसी आय के रिटर्न में आय की गणना के लिए ऐसी राशि को ध्यान में रखा है; और

(iii) ऐसी आय के रिटर्न में उसके द्वारा घोषित आय पर देय कर का भुगतान कर दिया है, और वह व्यक्ति लेखाकार से इस आशय का प्रमाण पत्र ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करता है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है:

बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति से धारा 221 के तहत कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा, जब तक कि मूल्यांकन अधिकारी को यह विश्वास न हो जाए कि ऐसा व्यक्ति, अच्छे और पर्याप्त कारणों के बिना, ऐसे कर को काटने और भुगतान करने में विफल रहा है।

(1-ए) उप-धारा (1) के प्रावधानों के प्रतिकूल प्रभाव के बिना, यदि कोई ऐसा व्यक्ति,

प्रधान अधिकारी या कंपनी, जिसे उस उप-धारा में संदर्भित किया गया है, पूरे कर या उसके किसी हिस्से को नहीं काटता है या कटौती करने के बाद इस अधिनियम के तहत या उसके तहत अपेक्षित कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, - (i) ऐसे कर की राशि पर प्रत्येक महीने या महीने के हिस्से के लिए एक प्रतिशत की दर से उस तारीख से जिस दिन ऐसा कर कटौती योग्य था, उस तारीख तक जिस दिन ऐसा कर काटा जाता है; और

(ii) ऐसे कर की राशि पर प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए उस तिथि से जिसको ऐसा कर काटा गया था उस तिथि तक जिसको ऐसा कर वास्तव में चुकाया गया है डेढ़ प्रतिशत की दर से, और ऐसा ब्याज धारा 200 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार विवरण प्रस्तुत करने से पूर्व चुकाया जाएगा:

बशर्ते कि यदि कोई व्यक्ति, जिसमें कंपनी का प्रधान अधिकारी भी शामिल है, किसी निवासी को भुगतान की गई राशि पर या किसी निवासी के खाते में जमा की गई राशि पर इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार कर का पूरा या उसका कोई भाग काटने में विफल रहता है, लेकिन उसे उप-धारा (1) के पहले परंतुक के तहत चूककर्ता करदाता नहीं माना जाता है, तो खंड (i) के तहत ब्याज उस तारीख से देय होगा, जिस दिन ऐसा कर कटौती योग्य था, ऐसे निवासी द्वारा आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की तारीख तक। आगे यह भी प्रावधान है कि जहां उप-धारा (1) के तहत चूक के लिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई आदेश दिया जाता है, वहां उस व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश के अनुसार ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

(2) जहां कर का भुगतान पूर्वोक्त रूप से कटौती के बाद नहीं किया गया है, उप-धारा (1-ए) में निर्दिष्ट कर की राशि और उस पर साधारण ब्याज की राशि, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति या कंपनी की सभी परिसंपत्तियों पर भार होगी। (3) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जाएगा, जिसमें किसी व्यक्ति को भारत में निवासी किसी व्यक्ति से कर का पूरा या उसका कोई भाग काटने में विफल रहने के कारण चूककर्ता करदाता माना जाए, उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से सात वर्ष की अवधि के पश्चात्, जिसमें भुगतान किया गया हो या क्रेडिट दिया गया हो।

(4) धारा 153 की उपधारा (3) के उपखंड (ii) और धारा 153 के स्पष्टीकरण 1 के उपबंध, जहां तक हो सके, उपधारा (3) में निर्धारित समय सीमा पर लागू होंगे।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, पद “लेखाकार” का वही अर्थ होगा, जो धारा 288 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में दिया गया है।

“203. कर के लिए प्रमाण-पत्र - (1) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार कर काटने वाला प्रत्येक व्यक्ति, राशि जमा करने या भुगतान करने के समय से, या, जैसा भी मामला हो, किसी शेयरधारक को किसी लाभांश के भुगतान के लिए चेक या वारंट जारी करने के समय से निर्धारित अवधि के भीतर, उस व्यक्ति को जिसके खाते में ऐसा क्रेडिट दिया गया है या जिसे ऐसा भुगतान किया गया है या चेक या वारंट जारी किया गया है, इस आशय का प्रमाण-पत्र देगा कि कर काट लिया गया है और इस प्रकार कटौती की गई राशि, जिस दर से कर काटा गया है और ऐसे अन्य विवरण जो निर्धारित किए जा सकते हैं, निर्दिष्ट करेंगे। (2) धारा 192 की उपधारा (1ए)

में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो नियोक्ता है, ऐसी अवधि के भीतर, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, उस व्यक्ति को, जिसकी आय के संबंध में कर का ऐसा भुगतान किया गया है, इस आशय का एक प्रमाणपत्र देगा कि कर केंद्रीय सरकार को भुगतान कर दिया गया है, और भुगतान की गई राशि, जिस दर पर कर का भुगतान किया गया है और ऐसे अन्य विवरण निर्दिष्ट करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

8. आयकर नियम, 1962 के नियम 31 के तहत, जेबीवीएनएल को स्रोत पर कर कटौती का विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि से 15 दिनों के भीतर फॉर्म-16ए में स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र जारी करना आवश्यक है। आयकर नियम, 1962 का नियम 31 नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

31. धारा 203 के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना।- (1) अध्याय X V II-B के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण-पत्र या धारा 192 की उप-धारा (IA) के अन्तर्गत कर्मचारी की ओर से नियोक्ता द्वारा कर भुगतान का प्रमाण-पत्र - (क) प्रपत्र संख्या 16 में होगा, यदि कर की कटौती या भुगतान धारा 192 (तथा धारा 194 पी) के अन्तर्गत है; तथा (ख) प्रपत्र संख्या 16A में होगा, यदि कटौती अध्याय X V II-B के किसी अन्य प्रावधान के अन्तर्गत है। (2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र में निम्नलिखित निर्दिष्ट किया जाएगा: - (क) कटौतीकर्ता का वैध स्थायी खाता संख्या (पीएएन); (ख) कटौतीकर्ता का वैध कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या (टीएएन); (ग) (i) पुस्तक पहचान संख्या या संख्याएं, जहां सरकारी कार्यालय के मामले में कटौती किए गए कर का जमा चालान प्रस्तुत किए बिना किया जाता है; (ii) बैंक के माध्यम से भुगतान के मामले में चालान पहचान संख्या या संख्याएं; (घ) (i) स्रोत पर कर कटौती के प्रासंगिक त्रैमासिक विवरण की रसीद संख्या जो नियम 21ए के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की जाती है; (ii) यदि खंड (i) में निर्दिष्ट विवरण "वेतन" शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य आय से स्रोत पर कर कटौती के लिए है, तो सभी प्रासंगिक त्रैमासिक विवरणों की रसीद संख्याएं। (3) नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट प्रपत्रों में प्रमाण पत्र कर्मचारी या आदाता को, जैसा भी मामला हो, कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट आवधिकता के अनुसार और उक्त तालिका के कॉलम (4) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट समय तक प्रस्तुत किए जाएंगे:-

सारणी

क्रम सं.	प्रपत्र सं.	आवधिकता	
(1)	(2)	(3)	
1.	16	वार्षिक	उस वित्तीय वर्ष के ठीक बाद वाले वित्तीय वर्ष की 15 जून तक जिसमें आय का भुगतान किया गया था और कर काटा गया था
2.	16ए	त्रैमासिक	नियम 31ए के तहत स्रोत पर कर कटौती का

			विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर।
--	--	--	--

9. आयकर अधिनियम की धारा 271-सी में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति स्रोत पर कर का पूरा या उसका कोई भाग काटने में विफल रहता है, तो उसे जुर्माना देना होगा। तथा धारा 276-बी स्रोत पर काटे गए कर का भुगतान केंद्र सरकार के खाते में न करने को दंडनीय बनाती है। धारा 271-सी और 276-बी के अंतर्गत प्रावधान इस प्रकार हैं:

271-सी. स्रोत पर कर कटौती करने में विफलता के लिए जुर्माना.--(1) यदि कोई व्यक्ति--

(क) अध्याय X V II-बी के प्रावधानों द्वारा या उसके अंतर्गत अपेक्षित कर का पूरा या उसका कोई भाग काटने में विफल रहता है; या

(ख) निम्नलिखित के द्वारा या उसके अंतर्गत अपेक्षित कर का पूरा या उसका कोई भाग भुगतान करने या भुगतान सुनिश्चित करने में विफल रहता है,-

(i) धारा 115-ओ की उपधारा (2); * * *

(ii) धारा 194-बी का प्रावधान;

(iii) धारा 194-आर की उपधारा (1) का पहला प्रावधान; या

(iv) धारा 194-एस की उपधारा (1) का प्रावधान; या (v) धारा 194-बी.ए. की उपधारा (2) के अधीन है, तो ऐसा व्यक्ति कर की उस राशि के बराबर राशि, जिसे वह व्यक्ति पूर्वोक्त अनुसार काटने, भुगतान करने या भुगतान सुनिश्चित करने में विफल रहा है, शास्ति के रूप में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। (2) उपधारा (1) के अधीन लगाया जाने वाला कोई भी शास्ति संयुक्त आयुक्त द्वारा लगाया जाएगा।

276-बी. अध्याय X II-डी या X V II-बी के तहत केंद्र सरकार के खाते में कर का भुगतान करने में विफलता.- यदि कोई व्यक्ति * * * को भुगतान करने में विफल रहता है, - (ए) केंद्र सरकार के खाते में, उसके द्वारा स्रोत पर कटौती किए गए कर का भुगतान अध्याय X V II-बी के प्रावधानों के तहत या उसके द्वारा अपेक्षित के रूप में; या (बी) कर का भुगतान या केंद्र सरकार के खाते में कर का भुगतान सुनिश्चित करना, जैसा कि - (i) धारा 115-ओ की उप-धारा (2); (ii) धारा 194-बी का प्रावधान; (iii) धारा 194-आर की उप-धारा (1) का पहला प्रावधान; (iv) धारा 194-एस की उप-धारा (1) का प्रावधान; या (v) धारा 194-बी.ए. की उपधारा (2) के तहत, उसे कम से कम तीन महीने की कठोर कारावास की सजा दी जाएगी, लेकिन यह अवधि सात साल तक की हो सकेगी और जुर्माना भी देना होगा।

10. एक से अधिक बार, जेबीवीएनएल ने यह रुख अपनाया है कि उसने आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार 2,90,32,000/- रुपए अपने पास रखे हैं, जिसमें माल की आपूर्ति के लिए किए गए भुगतान के विरुद्ध टीडीएस कटौती नहीं करने का आरोप लगाया गया है। जवाबी हलफनामे में, जेबीवीएनएल ने रोकी गई राशि को "वापस रखी गई" राशि के रूप में लेबल किया है और इसे याचिकाकर्ता-फर्म को जारी किया जाएगा या 10 अक्टूबर 2017 और 6 नवंबर 2017 की मांग नोटिस के खिलाफ दायर अपील के निपटारे के बाद टीडीएस प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। याचिकाकर्ता-फर्म ने एक स्पष्ट बयान दिया है कि उसने आयकर रिटर्न दाखिल किया है और सभी आयकर

देनदारियों का भुगतान किया है और, जेबीवीएनएल द्वारा रोकी गई राशि उसके कर दायित्व से अधिक है। रिट याचिका का पैराग्राफ नंबर 20 नीचे उद्धृत है:

“20. यह कहा गया है कि इसके बाद, याचिकाकर्ता ने दिनांक 21.09.2018 को संदर्भ संख्या ए सी पी एल / जे बी वी एन एल / डी डी यू जी जे वाई /2018-19/998 के माध्यम से एक पत्र लिखा। जिसमें याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी जेबीवीएनएल का ध्यान याचिकाकर्ता से एकत्र किए गए अतिरिक्त टीडीएस की ओर आकर्षित किया था। यह भी कहा गया था कि याचिकाकर्ता को प्रतिवादी जेबीवीएनएल द्वारा काटे गए/रखे गए/रोके गए टीडीएस का कोई क्रेडिट नहीं मिला है क्योंकि यह याचिकाकर्ता के फॉर्म 26 A S में परिलक्षित नहीं हुआ था। इसके अलावा, यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने पहले ही आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है और सभी आयकर का भुगतान कर दिया है और इसलिए, प्रतिवादी जेबीवीएनएल से एकत्र किए गए अतिरिक्त टीडीएस के कारण रोकी गई राशि को जारी करने का अनुरोध किया है।”

11. याचिकाकर्ता फर्म द्वारा दिए गए उपरोक्त कथन के जवाब में, जेबीवीएनएल द्वारा निम्नलिखित रुख अपनाया गया है:

“13. यह कहा और प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तर के तहत रिट याचिका के पैराग्राफ 20 में दिए गए कथन के संबंध में कि सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप आयकर विभाग द्वारा डिमांड नोटिस के माध्यम से मांगी गई राशि याचिकाकर्ता के 26एस में प्रतिबिंबित नहीं हो रही थी, जिसे अपील के परिणाम के बाद टीडीएस की उचित वापसी के साथ विभाग के पास जमा किया जाएगा, जिसका इस जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 1 में अधिक विस्तार से वर्णन किया गया है।”

12. हमारी राय में, जेबीवीएनएल को जारी किया गया डिमांड नोटिस कि उसने टीडीएस कटौती नहीं करने में चूक की है, जेबीवीएनएल को किसी भी अधिकार या यहां तक कि ठेकेदार के चालू बिलों से एक निश्चित राशि रोकने का बहाना नहीं दे सकता है। यह काफी उत्सुकता की बात है कि जेबीवीएनएल सीआईटी (अपील) के समक्ष यह रुख अपनाना चाहता है कि वह सामग्री की आपूर्ति के लिए ठेकेदार के चालू बिलों से 2% टीडीएस काटने के लिए बाध्य नहीं था और दूसरी ओर, उसने उस हिसाब से 2% टीडीएस कटौती के भुगतान के लिए 2,90,32,000 रुपये अपने पास रख लिए हैं। यह भी प्रासंगिक है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से शुरू होने वाली जेबीवीएनएल की कटौती 2,90,32,000 रुपये तक जमा हो गई है, लेकिन उसने उक्त राशि आयकर विभाग के पास जमा नहीं की है। याचिकाकर्ता फर्म के चालू बिलों से रोकी गई राशि सट्टा है और जेबीवीएनएल द्वारा एक तरह का दांव है। आयकर विभाग के साथ मुकदमेबाजी के उद्देश्य से 2,90,32,000/- रुपये को “वापस रखी गई” राशि के रूप में रोकने का जेबीवीएनएल के पास कानूनी तौर पर कोई अधिकार नहीं है। इसलिए 2,90,32,000/- रुपये रोकने की जेबीवीएनएल की कार्रवाई अवैध और निंदनीय है; इस पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए।

13. जेबीवीएनएल की ओर से उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता श्री राजीव रंजन तथा विद्वान वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता श्री सचिन कुमार ने दलील दी कि अनुबंध की सामान्य शर्तों की धारा 10 के अनुसार, जेबीवीएनएल ने आयकर विभाग द्वारा कर की मांग के विरुद्ध कटौती की है।

14. अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 10 में निम्नानुसार प्रावधान है:

10. कर और शुल्क

10.1 ठेकेदार नियोक्ता को अनुबंधित आपूर्ति की डिलीवरी तक कानूनी रूप से देय/उपगत सभी करों, शुल्कों, लाइसेंस शुल्क और अन्य ऐसे शुल्कों के भुगतान के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

यदि ऐसे करें और शुल्कों या किसी अन्य लागू करें और शुल्कों के लिए कटौती करना वैधानिक आवश्यकता है, तो नियोक्ता द्वारा ऐसा किया जाएगा और इसके लिए ठेकेदार को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

10.2 ठेकेदार अपने व्यक्तियों या अपने किसी भी कर्मचारी की आय पर लगाए जाने वाले करों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और नियोक्ता के खिलाफ किए जाने वाले किसी भी दावे के खिलाफ नियोक्ता को क्षतिपूर्ति और हानिरहित रखेगा। नियोक्ता भारतीय आयकर अधिनियम के तहत ठेकेदार या उसके कर्मियों के लिए करों के संबंध में कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है। यदि यह भारतीय आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनिवार्य है, तो नियोक्ता द्वारा स्रोत पर आयकर की कटौती की जाएगी।

10.3 नियोक्ता और ठेकेदार के बीच सीधे लेन-देन के मामले में, ई एक्स डब्ल्यू मूल्य में सभी लागत के साथ-साथ शुल्क और कर (जैसे, सीमा शुल्क और लेवी, शुल्क, बिक्री कर/वैट आदि) शामिल नहीं हैं, जो संयंत्र और उपकरण में शामिल या शामिल किए जाने वाले घटकों, कच्चे माल और उनके उपभोग के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी अन्य वस्तु पर चुकाए गए या देय हैं।

'प्रत्यक्ष लेन-देन' के तहत उपकरण/वस्तुओं के लिए बिक्री कर/वैट, उत्पाद शुल्क, स्थानीय कर और अन्य लेवी, जिसमें गंतव्य स्थल/राज्य के लिए लागू ऑक्टोई शामिल है, ई एक्स डब्ल्यू मूल्य में शामिल नहीं हैं। ये राशियाँ ठेकेदार द्वारा की गई आपूर्तियों पर नियोक्ता द्वारा (बाद में होने वाले बदलाव के साथ, यदि कोई हो) देय होंगी, लेकिन नियोक्ता और ठेकेदार के बीच लेन-देन पर कर देयता तक सीमित होंगी।

खरीदे गए तैयार आइटमों के संबंध में, जिन्हें उप-विक्रेता के कार्यों से सीधे परियोजना स्थल (ट्रांजिट में बिक्री) पर भेजा जाएगा, ई एक्स डब्ल्यू मूल्य में सभी लागतों के साथ-साथ शुल्क और कर (जैसे, सीमा शुल्क और शुल्क, शुल्क, बिक्री कर/वैट आदि) शामिल हैं, जो भुगतान किए गए या देय हैं और ऐसे कोई भी कर, अतिरिक्त शुल्क ठेकेदार के खाते में जाएंगे और नियोक्ता द्वारा इस संबंध में कोई अलग दावा नहीं किया जाएगा। अपेक्षित बिक्री कर घोषणा प्रपत्र निम्नानुसार जारी किए जाएंगे:

क) जेबीवीएनएल अपने अधिकार क्षेत्र में अनुबंधों के लिए ठेकेदार को आवश्यक फॉर्म जारी करेगा। इसके अलावा, (i) खरीदे गए तैयार उपकरणों/वस्तुओं की ईएक्सडब्ल्यू कीमत 'ऑफ द सेल्फ' आइटम के रूप में या ठेकेदार के कार्यों से सीधे भेजी गई है, जिसमें सभी लागत और शुल्क और कर (जैसे, सीमा शुल्क और लेवी, शुल्क बिक्री कर/वैट आदि) शामिल नहीं हैं और इस संबंध में नियोक्ता द्वारा कोई अलग दावा नहीं किया जाएगा। नियोक्ता, हालांकि, अपेक्षित बिक्री कर घोषणा फॉर्म जारी करेगा। यदि देश में ठेकेदार को कोई कर छूट, कटौती, भत्ते या विशेषाधिकार उपलब्ध हो सकते हैं, जहां साइट स्थित है, तो नियोक्ता अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करके ठेकेदार को अधिकतम स्वीकार्य सीमा तक ऐसी कर बचत से लाभान्वित करने में सक्षम करेगा। आपूर्ति की गई वस्तुओं में सीएसटी को शामिल करने पर फॉर्म-सी लागेगा। संबंधित मुख्य अभियंता की सिफारिश पर बाहरी राज्य सामग्री के लिए जेबीवीएनएल द्वारा सड़क परमिट जारी किया जाएगा। बिक्री कर के भुगतान/प्रतिपूर्ति के लिए, जहाँ भी लागू हो, ठेकेदार के कार्यों से सीधे किए गए प्रेषण के संबंध में, ठेकेदार द्वारा बनाए गए चालान को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा और वैट के भुगतान/प्रतिपूर्ति के लिए, ठेकेदार द्वारा बनाए गए वैट योग्य चालान को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया

जाएगा। इसी तरह, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पूर्व-संख्यांकित चालान को उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए साक्ष्य के रूप में माना जाएगा।

10.4 गंतव्य स्थल/राज्य के लिए आपूर्ति की सभी वस्तुओं पर लागू चुंगी, जिसमें खरीदी गई तैयार वस्तुएँ शामिल हैं, जिन्हें उप-विक्रेता के कार्यों से सीधे नियोक्ता के स्थल (ट्रांजिट में बिक्री) पर भेजा जाएगा, अनुबंध मूल्य में शामिल नहीं हैं। आपूर्ति की सभी वस्तुओं के संबंध में लागू चुंगी, नियोक्ता द्वारा दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने के अधीन ठेकेदार को अलग से प्रतिपूर्ति की जाएगी।

10.5 नियोक्ता सेवा कर के कारण कोई देयता नहीं उठाएगा। हालाँकि, नियोक्ता नियमों के अनुसार स्रोत पर ऐसे कर की कटौती करेगा और ठेकेदार को आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

10.6 कार्य अनुबंध पर बिक्री कर/वैट, टर्नओवर कर या भारत में की जाने वाली सेवाओं के लिए बिक्री कर/वैट अधिनियम के तहत लागू कोई अन्य समान कर अनुबंध मूल्य में शामिल है और नियोक्ता इस खाते में कोई देयता नहीं उठाएगा। हालाँकि, नियोक्ता नियमों के अनुसार स्रोत पर ऐसे करों की कटौती करेगा और ठेकेदार को स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

10.7 अनुबंध के प्रयोजन के लिए, यह सहमति है कि अनुबंध अनुबंध के अनुच्छेद 2 (अनुबंध मूल्य और भुगतान की शर्तें) में निर्दिष्ट अनुबंध मूल्य बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से सात (07) दिन पहले की तिथि पर प्रचलित करें, शुल्कों, शुल्कों और प्रभारों पर आधारित है (जिसे इसके बाद इस जीसीसी उप-खंड 10.7 में "कर" कहा जाता है)। यदि कर की कोई दर बढ़ाई या घटाई जाती है, एक नया कर पेश किया जाता है, एक मौजूदा कर को समाप्त कर दिया जाता है, या अनुबंध के निष्पादन के दौरान किसी भी कर की व्याख्या या आवेदन में कोई परिवर्तन होता है, जो अनुबंध के निष्पादन के संबंध में ठेकेदार पर लगाया गया था या लगाया जाएगा, अनुबंध मूल्य का एक न्यायसंगत समायोजन अनुबंध मूल्य में किसी भी ऐसे परिवर्तन को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए या उसमें से कटौती करके किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, जीसीसी खंड 31 (कानूनों और विनियमों में परिवर्तन) के अनुसार। हालाँकि, ये समायोजन नियोक्ता और ठेकेदार के बीच सीधे लेन-देन तक ही सीमित रहेंगे, जिसके लिए कर और शुल्क नियोक्ता द्वारा अनुबंध के अनुसार प्रतिपूर्ति योग्य हैं। ये समायोजन ठेकेदार द्वारा कच्चे माल, मध्यवर्ती घटकों आदि की खरीद पर लागू नहीं होंगे और उप-विक्रेता के कार्यों से साइट पर सीधे भेजे गए खरीदे गए सामानों पर भी लागू नहीं होंगे।

कच्चे माल, मध्यवर्ती घटकों आदि और खरीदी गई वस्तुओं के संबंध में, न तो नियोक्ता और न ही ठेकेदार, अनुबंध के निष्पादन के दौरान कर की दर में वृद्धि या कमी, एक नया कर लागू होने या मौजूदा कर को समाप्त करने के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे के लिए हकदार होंगे।

जी.सी.सी. का खंड 10.1 यह प्रावधान करता है कि ठेकेदार नियोक्ता को अनुबंधित आपूर्ति की डिलीवरी तक कानूनी रूप से देय या व्यय किए जाने वाले सभी करों, शुल्कों, लाइसेंस शुल्कों और अन्य ऐसे शुल्कों के भुगतान के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। इसमें आगे यह भी प्रावधान है कि जहां ऐसे करों और शुल्कों या किसी अन्य लागू करों और शुल्कों के लिए कटौती करना वैधानिक आवश्यकता है, वहीं नियोक्ता द्वारा ऐसा किया जाएगा और ठेकेदार को इसके लिए एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। आयकर अधिनियम की धारा 201 के तहत, 2% टी.डी.एस. कटौती करना

नियोक्ता का वैधानिक कर्तव्य है। इसके अलावा, जी.सी.सी. के खंड 10.1 के अनुसार, ऐसी कटौती करने पर ठेकेदार को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। जीसीसी की धारा 10.7 में यह प्रावधान है कि कानून में परिवर्तन की स्थिति में यदि अनुबंध के निष्पादन के दौरान कोई नया कर लगाया जाता है या कर की दर बढ़ाई या घटाई जाती है, तो अनुबंध मूल्य में न्यायसंगत समायोजन किया जाएगा ताकि अनुबंध मूल्य में वृद्धि या कटौती करके ऐसे किसी भी परिवर्तन को पूरी तरह ध्यान में रखा जा सके, जैसा भी मामला हो। जेबीवीएनएल ने जीसीसी की धारा 10.1 के तहत अपने स्वयं के निर्धारण का पालन नहीं किया है और यह धारा 10.7 पर बहुत ही अनुचित निर्भरता रखना चाहता है, जो वर्तमान जैसी स्थिति में बिल्कुल भी लागू नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई नई कर देयता बनाई गई है जिसके लिए अनुबंध मूल्य में उचित और न्यायसंगत समायोजन की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता-फर्म ने विशेष रूप से दलील दी है कि उसने आयकर रिटर्न दाखिल किया है और पहले ही करों का भुगतान किया है जिसमें उसके चालू बिलों से अवैध 2% प्रतिधारण शामिल है।

16. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अनुबंध की स्पष्ट शर्तें हमेशा पक्षों की मंशा के संबंध में अंतिम शब्द होती हैं। "ओ एन जी सी लिमिटेड बनाम सॉ पाइप्स लिमिटेड" (2003) 5 एससीसी 705 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि पक्षों की मंशा समझौते में इस्तेमाल किए गए शब्दों से समझी जानी चाहिए। "महाबीर ऑटो स्टोर्स बनाम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन" (1990) 3 एससीसी 752 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य या उसके साधन 'राज्य' हैं और वाणिज्यिक लेनदेन में भी उनके कार्य उचित, निष्पक्ष और न्यायसंगत होने चाहिए। "महाबीर ऑटो स्टोर्स" में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे संकेत दिया कि राज्य और उसके साधनों की ओर से न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित होने की आवश्यकता उन मामलों में भी लागू होती है जहां कोई औपचारिक अनुबंध दर्ज नहीं किया गया है।

17. किसी अन्य व्यक्ति के धन या संपत्ति को अनुचित तरीके से अपने पास रखना न्याय, समानता और अच्छे विवेक के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। याचिकाकर्ता-फर्म के चालू बिलों से अनधिकृत कटौती स्पष्ट रूप से अवैध है। ऐसी कटौतियों के कारण याचिकाकर्ता-फर्म को नुकसान हुआ, जिसने अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया, लेकिन उसे 2,90,32,000/- रुपये से वंचित होना पड़ा और इस तरह उसे व्यवसाय या कम से कम ब्याज का नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी ओर, जेबीवीएनएल को अनुचित तरीके से लाभ हुआ और उसे याचिकाकर्ता-फर्म को वापस लौटाने की आवश्यकता है। इसलिए 2,90,32,000/- रुपये की वापसी पर ब्याज अवश्य लगेगा। "इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो-लीगल एक्शन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया" (2011) 8 एससीसी 161 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि चक्रवृद्धि ब्याज और दंडात्मक लागत लगाकर अनुचित लाभ को बेअसर करना न्यायालय का अनिवार्य कर्तव्य है। कथित निर्णय के पैराग्राफ संख्या 178 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:

"178. पूर्ण न्याय करने, गलत कामों को रोकने, गलत काम या देरी के लिए प्रोत्साहन को हटाने और व्यावहारिक रूप से धन के समय मूल्य, प्रतिपूर्ति और अन्यायपूर्ण संवर्धन की अवधारणाओं को लागू करने के लिए - या बस समतल करने के लिए - एक सुविधाजनक तरीका ब्याज की गणना करना है। लेकिन यहाँ ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर की जानी चाहिए - और सरल आधार पर नहीं - क्योंकि बाद में गलत काम करने वाले के हाथों में बहुत सारे अनावश्यक लाभ रह जाते हैं।"

18. झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग, रांची (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियमन, 2015 के खंड 10.7.4 के अनुसार, उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई किसी भी अतिरिक्त राशि पर भुगतान की

जाने वाली ब्याज दर, विलंब भुगतान अधिभार पर उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई ब्याज दर के बराबर है। इसलिए, जे बी वी एन एल विनियमन 2015 के खंड 10.7.4 के अनुसार रोकੀ गई राशि 2,90,32,000/- पर ब्याज का भुगतान करेगा, जो नीचे उद्धृत है:

10.7.4 यदि उपभोक्ता ने कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान किया है, तो उसे 15 दिनों के भीतर उपभोक्ता को वापस कर दिया जाएगा या यदि उपभोक्ता चाहे तो दो बाद के बिलों में समायोजित कर दिया जाएगा। वितरण लाइसेंसधारी उपभोक्ता को भुगतान की तिथि से लेकर बाद के बिलों में वापसी या समायोजन की तिथि तक ऐसे गलत बिलिंग के कारण बकाया अतिरिक्त राशि पर टैरिफ के अनुसार विलंब भुगतान अधिभार के बराबर दर पर ब्याज शुल्क का भुगतान करेगा।

19. लागत लगाने के संबंध में, हम संकेत दे सकते हैं कि 14 मार्च 2024 को, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया है: "याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एम.एस. मित्तल, जेबीवीएनएल के विद्वान वरिष्ठ स्थायी वकील श्री सचिन कुमार और आयकर विभाग के विद्वान वकील श्री अनुराग विजय को संक्षेप में सुनने के बाद, इस न्यायालय ने प्रथम दृष्टया राय बनाई है कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए बिलों से 2% टीडीएस कटौती के कारण कथित रूप से 2,90,32,000/- रुपये की राशि को रोकना कानून में किसी भी अधिकार के बिना है यदि उक्त राशि आयकर विभाग के पास जमा नहीं की जाती है। 2. जवाबी हलफनामे में, जेबीवीएनएल द्वारा लिया गया यह रुख कि आयकर अधिनियम, 1961 के तहत भविष्य की देनदारी को पूरा करने के लिए उपरोक्त राशि को "रख-रखाव राशि" के रूप में रखा गया है, भी अनुचित प्रतीत होता है। आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों पर सरसरी निगाह डालने पर पता चलता है कि एक बार टीडीएस देयता के लिए राशि काट लेने के बाद उसे जमा कर दिया जाना चाहिए था, ताकि करदाता को अपने आयकर रिटर्न में इसका लाभ मिल सके। 3. हालांकि, जेबीवीएनएल के विद्वान वरिष्ठ स्थायी वकील श्री सचिन कुमार के अनुरोध पर, इस मामले को एक सप्ताह के लिए स्थगित किया जाता है, ताकि जेबीवीएनएल इस मामले में सचेत निर्णय ले सके कि याचिकाकर्ता के चालू बिलों से काटी गई 2,90,32,000 रुपये की राशि जमा की जाए या नहीं। 4. उस उद्देश्य के लिए, यह मामला 21 मार्च 2024 को पोस्ट किया जाएगा।

20. इसके जवाब में एक पूरक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है जिसमें कहा गया है कि अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 10.1 और 10.7 के अनुसार, जिसके तहत ठेकेदार आयकर सहित किसी भी कर के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, जेबीवीएनएल को ठेकेदार को जारी की गई कीमत/बिल से ऐसी राशि समायोजित करने का अधिकार है। जेबीवीएनएल ने आगे कहा है कि यदि उसके द्वारा दायर अपील विफल हो जाती है तो उसे ब्याज और दंड के साथ पूरी राशि जमा करनी होगी और फिर टीडीएस रिटर्न दाखिल करना होगा और इसके लिए प्रमाण पत्र यानी फॉर्म-16ए तैयार करके ठेकेदार को जारी करना होगा। मामले की परिस्थितियों में, हम मानते हैं कि जेबीवीएनएल द्वारा लिया गया रुख सद्भावना से रहित है; संक्षेप में कहें तो परोक्ष उद्देश्य से प्रेरित है।

21. बिना किसी उचित कारण के मुकदमा शुरू करने वाले या झूठे और तुच्छ बचाव का सहारा लेने वाले पक्ष पर जुर्माना लगाना बेईमान वादी को हतोत्साहित करने के लिए आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए, न्यायालय को ऐसा जुर्माना लगाना आवश्यक है जिससे वादी को कोई भी काल्पनिक दावा या बचाव पेश करने से पहले दो बार सोचना पड़े। "सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन (II) बनाम भारत संघ" (2005) 6 एससीसी 344 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से निर्णय दिया:

"37. इस तथ्य पर न्यायिक ध्यान दिया जा सकता है कि कई बेईमान पक्ष इस तथ्य का लाभ उठाते हैं कि या तो लागत नहीं दी जाती है या असफल पक्ष के खिलाफ नाममात्र की लागत दी

जाती है। दुर्भाग्य से, पक्षों को अपनी लागत स्वयं वहन करने का निर्देश देना एक प्रथा बन गई है। बड़ी संख्या में मामलों में, संहिता की धारा 35(2) के बावजूद ऐसा आदेश पारित किया जाता है। इस तरह की प्रथा तुच्छ मुकदमों को दायर करने को भी प्रोत्साहित करती है। यह तुच्छ बचाव को भी बढ़ावा देती है। इसके अलावा, जहाँ भी लागत दी जाती है, आमतौर पर वही वास्तविक नहीं होती है और नाममात्र की होती है। जब धारा 35(2) घटना के बाद लागत का प्रावधान करती है, तो यह निहित है कि लागत वही होनी चाहिए जो सफल पक्ष द्वारा उचित रूप से वहन की जाती है, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहाँ न्यायालय अपने विवेक से कारणों को दर्ज करके अन्यथा निर्देश दे सकता है। लागतें वास्तविक उचित लागतें होनी चाहिए, जिसमें सफल पक्ष द्वारा खर्च किया गया समय, परिवहन और आवास, यदि कोई हो, या मुकदमे से संबंधित न्यायालय शुल्क, वकील की फीस, टाइपिंग और अन्य लागतों के भुगतान के अलावा कोई अन्य आकस्मिक लागत शामिल हो। इन पहलुओं की जांच करना और जहाँ आवश्यक हो, अपेक्षित नियम, विनियम या अभ्यास निर्देश बनाना उच्च न्यायालयों का काम है, ताकि अधीनस्थ न्यायालयों के लिए पालन करने हेतु उचित दिशा-निर्देश प्रदान किए जा सकें।”

22. याचिकाकर्ता फर्म को अनावश्यक रूप से न्यायालय में घसीटा गया और वह भी जानबूझकर और उसकी ओर से कोई गलती न होने के बावजूद। न्यायालय में प्रस्तुत मुकदमे की फाइल से पता चलता है कि इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 14 मार्च 2024 के आदेश के संदर्भ में निर्णय जेबीवीएनएल के प्रबंध निदेशक के उच्चतम स्तर पर लिया गया है। इसलिए, हमारा स्पष्ट मत है कि जेबीवीएनएल पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाना चाहिए, जिसे प्रबंध निदेशक से वसूला जाएगा।

23. उपरोक्त शर्तों के तहत इस रिट याचिका को स्वीकार किया जाता है।

(श्री चन्द्रशेखर, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश)

(नवनीत कुमार, न्यायाधीश)

आर.के./निशांत
एएफआर

यह अनुवाद ज्ञान रंजन, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।